भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1444
बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को आरटीआई के अंतर्गत लाना

1444 श्रीमती सुलता देवः
श्री निरंजन बिशीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सहकारी समितियों को आरटीआई के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी नहीं, मान्यवर । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केवल लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है । तथापि, समिति के सदस्यों को समिति की कार्य प्रणाली और प्रबंधन से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2023 में यथासंशोधित) की संशोधित धारा 106 के अधीन सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध किया गया है ।

*****